PROCEEDINGS

REGIONAL CONFERENCE

ON

"STRENGTHENING THE STATE INSTITUTES OF PUBLIC ADMINISTRATION"

NOVEMBER 11TH -12TH 2021 AT LUCKNOW

सत्यमेव जयते

DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS AND PUBLIC GRIEVANCES

Strengthening the State Institutes of Public Administration के सम्बन्ध के दिनांक 11 व 12 नवम्बर, 2021 को Bankers Institute of Rural Development (BIRD) लखनऊ के सभागार में आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन का कार्यवृत्त

उपस्थित अधिकारी–

1. श्री आदिल जैनुलभाई, अध्यक्ष, कैपेसिटी बिल्डिंग, कमीशन।
2. श्री संजय सिंह, सचिव, डी0ए0आर0पी0जी0, भारत सरकार।
3. श्री एस0एन0 त्रिपाठी, महानिदेशक, आई0आई0पी0ए0
4. डा0 आर0 बालासुब्रामणियम, सदस्य, क्षमता निर्माण आयोग।
5. डा0 देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. श्री वी0 श्रीनिवास, विशेष सचिव, डी0ए0आर0पी0जी0।
7. श्री मनीष सबरवाल, कार्यकारी अधिकारी, लीज सर्विसेज।
8. श्री हेमांग जानी, सचिव, कैपेसिटी कमीशन।
9. सुश्री रश्मि चौधरी, अतिरिक्त सचिव, डी0ओ0पी0टी0।
10. श्रीमती रचना श्रीवास्तव, उप महानिदेशक, एन0आई0सी0।
11. श्री वेंकटेश्वर लू, महानिदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ।
12. श्रीमती दीप्ति गौर मुखर्जी, महानिदेशक, आर0वी0पी0 नरोन्हा अकादमी, भोपाल, मध्य प्रदेश।
13. श्री हरप्रीत सिंह, महानिदेशक, एन0सी0आर0एच0आर0डी0 संस्थान, तेलंगाना।
14. श्री सौरभ भगत, महानिदेशक, जे0 एण्ड के0 इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड रूरल डेवलपमेंट, श्रीनगर, जम्मू एण्ड कश्मीर।
15. श्री श्रीनिवास आर0 कटिकिथाला, निदेशक, लाल बहादुर शास्त्रीय राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी।
16. सुश्री सुनीता रानी, प्रोफेसर, लाल बहादुर शास्त्रीय राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी।
17. डा0 हिताशी लोमश, निदेशक, एस0एस0एफ0एस0आई0।

देश के अन्य प्रदेशों के सी0टी0आई0 एवं ए0टी0आई0 के अधिकारीगण (सूची संलग्न)

दिनांक 11 व 12 नवम्बर, 2021 को **Bankers Institute of Rural Development (BIRD),** लखनऊ के सभागार में आयोजित उक्त दो दिवसीय ''राज्य लोक प्रशासन संस्थान के सुदृढ़ीकरण'' विषय पर एक सम्मेलन/कार्यशाला का उद्घाटन मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं केन्द्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। उद्घाटन के समय अन्य अधिकारी श्री वी0 श्रीनिवास, विशेष सचिव, डी0ए0आर0पी0जी0, भारत सरकार, श्री संजय कुमार सिंह, सचिव, डी0ए0आर0पी0जी0, भारत सरकार, श्री आदिल जैनुलभाई, अध्यक्ष, क्षमता निर्माण आयोग एवं डा0 देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन उपस्थित थे।

श्री संजय कुमार सिंह, सचिव, डीएआरपीजी द्वारा मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार एवं मा0 केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री जितेन्द्र सिंह का स्वागत किया गया एवं सम्मेलन के उद्देश्यों और उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने उद्घाटन अभिभाषण के लिए सबसे पहले डॉ. जितेंद्र सिंह को आमंत्रित किया। डॉ जितेंद्र सिंह, केन्द्रीय राज्य मंत्री ने पहले इस क्षेत्रीय सम्मेलन की सहमति के लिए माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। डॉ0 सिंह ने कोविड–19 के दौरान राज्य में मुख्यमंत्री के कामकाज और इलाहाबाद में कुंभ के प्रबंधन की प्रशंसा की।

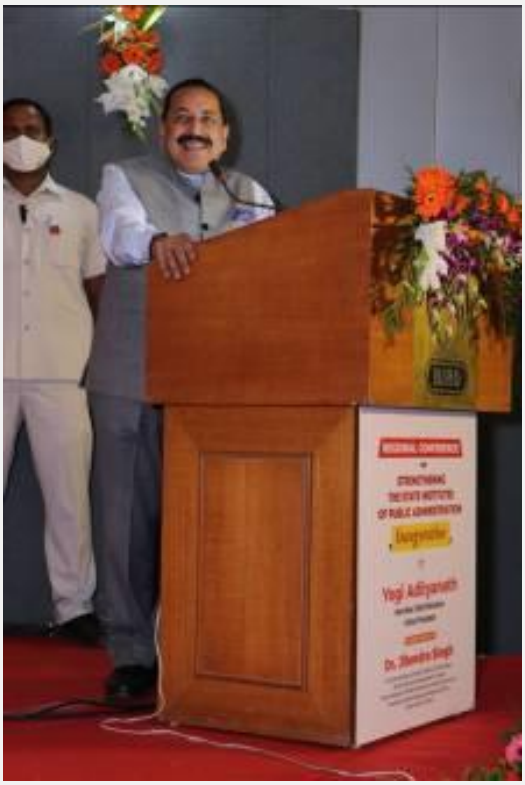

डॉ. सिंह ने अनुभव साझा किया कि स्वतंत्रता के बाद की अपेक्षाएं पूर्व से भिन्न हैं। ब्रिटिश सरकार के दौरान पहले सिविल सेवकों का उपयोग केवल अंग्रेजों के लिए कर–संग्रह के लिए किया जाता था, लेकिन अब स्वतंत्रता के बाद यह अधिक प्रबंधकीय और सुशासन आधारित हो गया है। जिम्मेदारियां अब दिन–ब–दिन बदल रही हैं। डॉ. सिंह ने अपने संबोधन के दौरान नौकरियों के लिए आवेदन करने के दौरान प्रमाण पत्र सत्यापन की समस्या साझा की, और माननीय प्रधान मंत्री के परामर्श के बाद उन्होंने प्रमाणपत्रों के स्व–प्रमाणन द्वारा इसे छूट दी। वर्तमान सरकार को युवाओं पर विश्वास है। डॉ0 सिंह ने प्रशंसा की, कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र पहले राज्य हैं, जिन्होंने इस तरह के स्व–प्रमाणन का पालन किया है और अपने राज्यों में लागू किया है। लिखित परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना जबकि साक्षात्कार में कम अंक केंद्र सरकार द्वारा अनुभव की जाने वाली एक और समस्या है। डॉ. सिंह ने साझा किया कि माननीय प्रधान मंत्री, भारत सरकार के मार्गदर्शन में भारत में साक्षात्कार प्रक्रिया को भी कुछ परीक्षाओं से समाप्त कर दिया गया है। प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के बाद, डी0ओ0पी0टी0 के शिकायत प्रकोष्ठ को अब शीघ्र उत्तर प्राप्त होने के कारण अधिक संख्या में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। अब सरकारी कार्यादेश वेबसाइट पर होस्ट किए जाते हैं, जो तत्सम्बन्धी कार्यवाही को आसान बनाता है। डॉ0 सिंह को उम्मीद थी कि सिविल सेवकों को ''रूल बेस'' के बजाय ''रोल बेस'' बनना चाहिए। डॉ0 सिंह ने बेरोजगार युवाओं के लिए जॉब प्राप्त करना आसान बनाने के लिए सभी पदों के सभी विभागों के लिए पी0ई0टी0 टेस्ट (प्रारम्भिक योग्यता टेस्ट) के बारे में विचार साझा किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि ब्व्टप्क्.19 ने ई–ऑफिस को एक नया आयाम दिया है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप ''कम उपस्थिति और अधिकतम उत्पादन'' हुआ है। डॉ0 सिंह ने प्रसन्नता व्यक्त की कि वह समय चला गया है जब हम अपने आई.पी.एस. अधिकारी को प्रशिक्षित करने के लिए विदेश भेजते हैं, अब भारत में, डीओपीटी दूसरे देश के सिविल सेवकों को प्रशिक्षण दे रहा है। उन्हें उम्मीद है कि इस सम्मेलन से लोक सेवकों को जनता की आवश्यकता के अनुसार अपनी प्रतिबद्धताओं को सुधारने में मदद मिलेगी।

माननीय मुख्यमंत्री ने डॉ. जितेंद्र सिंह, केन्द्रीय राज्य मंत्री, भारत सरकार का स्वागत किया। भारत सरकार का और उत्तर प्रदेश में इस तरह के क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए अधिकारियों को धन्यवाद दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता से जुड़ी कुछ समस्याओं जैसे पारदर्शी चयन प्रक्रिया, लोक सेवकों के रवैये और दुर्व्यव्हार, गोरखपुर में इंसेफेलाइटिस की समस्या, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे की कम उपलब्धता, लोक शिकायत समाधान पर कम ध्यान आदि की ओर इशारा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवनियुक्त सिविल सेवकों को ईमानदारी, सकारात्मकता और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू करना चाहिए ताकि जनता सुशासन का आनंद ले सके। उनका अनुभव था कि विभिन्न विभागों की उपलब्धियों की समीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कम जनशक्ति है और नियुक्तियों ध चयन प्रक्रिया को अदालतों में चुनौती दी जाती है। मा0 मुख्यमंत्री जी ने संबंधित अधिकारियों को न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत कर पारदर्शी चयन की अनुमति दिलाने के लिए तत्काल कार्रवाई एवं मार्गदर्शन किया। उन्होंने सिविल सेवकों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अधिकारियों को ब्व्टप्व्.19 और कुंभ मेले के दौरान दी गई मदद के लिए धन्यवाद दिया। अंतर–विभागीय समन्वय ने ब्व्टप्व्.19 की लड़ाई से उबरने में सफलता हासिल की है। कुंभ मेले के तीर्थयात्रियों के साथ पुलिस के बदलते रवैये और एप के माध्यम से असामाजिक, राष्ट्रविरोधी की पहचान के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा कुंभ मेले को सफल बनाया गया। मा0 मुख्यमंत्री जी ने सिविल सेवकों से निर्णय लेने की अपनी क्षमता बढ़ाने की अपेक्षा की। उन्होंने घोषणा की, कि आने वाले समय में हर जिले में बेरोजगार युवाओं की परीक्षा लेने के लिए और अधिक परीक्षा केंद्र होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उम्मीद जताई कि यह सम्मेलन समाधान के साथ आएगा और नए सिविल सेवक जनता के प्रति अपने दृष्टिकोण, ईमानदारी और समर्पण को अधिक से अधिक प्रभावी ढंग से सुधार सकेंगे।

डॉ. देवेश चतुर्वेदी, आईएएस, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा मुख्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गये। प्रथम दिन के समापन को सम्बोधन करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे यह आदेश हुआ है कि हमारे मा0 केन्द्रीय राज्य मंत्री जी की तरफ से यह घोषित करूं कि उनकी ओर से दो घोषणाएं की जा रही हैं। एक यह कि जिस तरह से गुड गवर्नेन्स इन्डेक्स से राज्यों का ब्वउचंतपेवद होकर उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनको आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार डी0आर0ए0पी0जी0 मदद करेगा और ब्वंबपजल ठनपसकपदह ब्वउउपेपवद के माध्यम से जिले का गुड गवर्नेन्स इन्डेक्स डेवलप कर तैयार किया जायेगा। इसमें हर जिले को कैसे परफार्म करना है तथा प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत करने में जिलाधिकारी व अधिकारी सहयोग करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि जैसे मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशों से ग्रिवान्स रिड्रेसल की बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है, उसी तरह की केन्द्रीय स्तर पर भी व्यवस्था है। इन दोनों व्यवस्थाओं को इन्टीग्रेट कर दें, जिससे कि जो केन्द्रीय पोर्टल पर शिकायत है, उनको राज्य के पोर्टल पर आकर उसका भी गुणात्मक रूप से हम लोग उसका समाधान कर सकें। इसे इन्टीग्रेट करने की भी व्यवस्था करेंगे। दोनों चीजों में उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा, जो इस तरह के इन्टीग्रेशन और इस तरह के डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेन्स इन्डेक्स के लिए इनीशिएटिव लेगा।

प्रथम सत्र श्री एस.एन. त्रिपाठी की अध्यक्षता में ''संकाय क्षमता निर्माण'' के लिए समर्पित था। श्री एस0एन0 त्रिपाठी, महानिदेशक, आई.आई.पी.ए. और डॉ. आर. बालासुब्रमण्यम, सदस्य, क्षमता निर्माण आयोग, डॉ. देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति और कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन ने क्षमता निर्माण पर चर्चा की। डॉ. आर. बालसुब्रमण्यम ने संकाय की आवश्यकता और महत्व, अच्छे संकाय के गुण और संकाय विकास के लिए क्षमता निर्माण आयोग के विषय में प्रकाश डाला। डॉ. देवेश चतुर्वेदी, आईएएस, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति और कार्मिक ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक प्रभाव (यूएनएआई) द्वारा प्राप्त क्षमता निर्माण की परिभाषा, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र द्वारा घटक, क्षमता निर्माण के संदर्भ में अनुमान, चुनौतियां और नीतिगत परिप्रेक्ष्य आदि के बारे में विचार रखे।

दूसरे सत्र में श्री प्रवीण परदेशी, सदस्य (प्रशासन), सी.बी.सी. की अध्यक्षता में ''भविष्य को बदलने – जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सार्वजनिक समाधान'' विषय पर श्री मनीष सबरवाल, टीम लीज सर्विसेज के कार्यकारी उपाध्यक्ष और श्री हेमंग जानी, सचिव, सीबीसी ने प्रतिभाग किया। प्रवीण परदेसी ने जनधन योजना, एक राष्ट्र एक कार्ड, आधार, डीबीटी, ऑनलाइन समाधान और ई–गवर्नेंस, और सुविधाएं, शिकायत पोर्टल, केसीसी, बालिका समृद्धि योजना, आदि जैसी सरकारी पहलों की ओर श्रोताओं का ध्यान आकर्षित किया। जनता की सुविधा के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने भविष्य को बदलने के लिए ''कर्मयोगी अभियान'' का नारा दिया है। इस पर उन्होंने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन भी दिया। उन्होंने देखा कि जनता की सुविधा के लिए अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। यह जानना आवश्यक है कि प्रशासन किस लिए है। ब्टप्क.19 के दौरान, माननीय प्रधान मंत्री की प्रेरणा पर, अंतर्विभागीय समन्वय ब्टप्क.19 और टीकाकरण में सफल रहा। उन्होंने व्यक्त किया कि प्रत्येक व्यक्ति में स्व–अध्ययन का गुण होता है और अधिकारी स्वयं को प्रशिक्षित करने और दिन–प्रतिदिन सीखने के लिए नियमित रूप से प्रयास कर रहा है, लेकिन क्षमता निर्माण सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर अधिक जोर दिया जाना है। श्री मनीष सबरवाल ने साझा किया कि केवल प्रशिक्षण प्रभावी नहीं है, लेकिन सही रणनीति, संरचना और स्टाफिंग, चयन, पोस्टिंग और स्थानांतरण, इनाम और पदोन्नति बहुत सारे बदलाव लाए जाने हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि बुनियादी ढांचे के पीपीपी मॉडल अधिक उत्पादकता, एम.एस.एम.ई. द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास से उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने सलाह दी कि सहभागी दृष्टिकोण, मोबाइल पर लगातार परीक्षण श्रृंखला, ऑनलाइन प्रमाणीकरण, और आध्यात्मिक सुधार आदि को भी प्रशिक्षण में शामिल किया जाना चाहिए।

तीसरा सत्र श्री संजय सिंह, सचिव, डीएआरपीजी की अध्यक्षता में सत्र "आई–गॉट ;प.ळवज्द्ध और ई–गवर्नेंस" को समर्पित था और स्पीकर श्रीमती रश्मि चौधरी, अपर सचिव, डी.ओ.पी.टी. ने ऑनलाइन विचार प्रस्तुत किए और श्रीमती रचना श्रीवास्तव, उप महानिदेशक, एन.आई.सी. ने भी प्रतिभाग किया। श्री संजय सिंह ने सत्र के दौरान "भविष्य के लिए तैयार–सिविल सेवा के लिए विचार" पर अपने विचार व्यक्त किए और भारत की सिविल सेवाओं की बाधाओं, नागरिक केंद्रितता में व्यवहार प्रशिक्षण, नियम आधारित और भूमिका आधारित, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं, क्षमता निर्माण योजनाओं पर प्रकाश डाला।

श्रीमती रश्मि चौधरी ने कर्मयोगी पर पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन पेश किया। श्रीमती चौधरी एनपीसीएससीबी ने एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण (आई–गाट) और ई–गवर्नेंस की आवश्यकता के बारे में अनुभव साझा किया। मिशन कर्मयोगी, संस्थागत संरचना, योग्यता ढांचा, मानव संसाधन प्रबंधन, ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए सामग्री विकास के लिए दिशा निर्देश, योग्यता विकास के लिए इण्ड टू इण्ड प्रक्रिया, जीवन चक्र में प्रशिक्षण हस्तक्षेप, निगरानी और मूल्यांकन आदि पर विचार साझा किए। तीसरे सत्र के दौरान श्रीमती रचना श्रीवास्तव, उप महानिदेशक, एन.आई.सी. द्वारा ई–ऑफिस, डिजिटल कार्य समाधान, कहीं से भी काम, सरकारी ई–प्रोक्योरमेंट, ई–नीलामी, ईएचआरएमएस, स्वागतम–ए गेटवे टू द गवर्नमेंट, ई–सर्विस,

सीपीजीआरएएमएस–केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण के बारे में ई–गवर्नेंस पर अनुभव प्रस्तुत किया। चौथा सत्र ''एटीआई में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना'' पर समर्पित था। श्री वी0 श्रीनिवास, विशेष सचिव, डीएआरपीजी की अध्यक्षता में और वक्ताओं में श्री एल वेंकटेश्वर लू, महानिदेशक, उपाम, श्रीमती दीप्ति गौर मुखर्जी, डीजी, आरवीपी, नरोन्हा एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, श्री हरप्रीत सिंह, डीजी (एफएसी), डॉ. एमसीआर एचआरडी इंस्टीट्यूट, तेलंगाना और श्री सौरभ भगत, *महानिदेशक, जे0 एण्ड के0 इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड रूरल डेवलपमेंट, श्रीनगर, जम्मू एण्ड श्रीनगर* और डॉ. पूनम सिंह, एन. सी.जी.जी. थे।

अपने मुख्य भाषण में श्री वी0 श्रीनिवास ने नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस (एनसीजीजी), डीएआरपीजी, भारत सरकार द्वारा की गई भूमिका और गतिविधियों के बारे में अपना विचार व्यक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण के लिए सहयोग, राज्यों के साथ सहयोग, भारतीय सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण, इसकी गतिविधियाँ, प्ज्म्ब – छब्ळळ गतिविधियाँ, सुशासन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाएँ, ऑनलाइन वर्चुअल कार्यशाला के दौरान महामारी, सुशासन वेबिनार, एन.सी.जी.जी. के अध्ययन और प्रकाशन पर विचार रखे।

श्री एल. वेंकटेश्वर लू, आई.ए.एस., महानिदेशक, उपाम ने कोर वैल्यू, स्थिरता और विकास मॉडल, सेन्टर ऑफ एक्सलेन्स बनाने हेतु आवश्यक विशेषज्ञता, और विभिन्न कार्यों पर विचार प्रस्तुत किए। श्री लू ने अपना अनुभव साझा करते हुए अपने वक्तब्य में कहा कि कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर राष्ट्र में अभूतपूर्व एक्सरसाईज हुई है। कर्मयोगी जब कर्म से जुड़ता है तब कर्म में कुशलता होनी चाहिए। कर्म में कुशलता क्या है, ऐसा कर्म करें, जिसमें शान्ति हो, सब शान्त रहें और खुशहाल हों। हम सब अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यह देखना होगा कि क्या 75 साल के बाद भी देश का आखिरी व्यक्ति खुशहाल है, बीच के चेहरे पर मुश्कान है। हम लोग इस बात पर चिन्तन कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपके अन्दर प्रतिबद्धता कितनी है। हमारे पूर्वजों ने कितना त्याग किया है इतना देश के बारे में सोचा, हमें वेतन मिलता है, अधिकार भी मिला हुआ है। हम लोगों को आधारभूत सुविधाएं भी दी जा रही हैं, फिर भी आदमी पावर, पोजीशन, अच्छा पोस्ट, बुरा पोस्ट की बात करता है। इसके चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपका स्तर क्या है– वैल्यूज, इथिक्स और मूल्य की बात करेंगे। आप किस स्तर पर हैं ;ीमतम कव लवन ैजंदकद्ध। हमारे ऋषि–मुनियों की जो भावना है यह बात हमको समझने की जरूरत है। बेसिक सेन्टर ऑफ एक्सलेन्स के लिए क्या–क्या चाहिए? दूरदर्शी नेतृत्व, विशेषज्ञता, सांगठनिक संस्कृति चाहिए। यदि हम स्वयं को सही करते हैं तो प्रतिबद्धता अच्छे परिणाम दे सकती है। अक्सर यह अनुभव किया जाता है कि नौकरशाह कर्म करते हैं लेकिन उसमें गुणवत्ता नहीं पाई जाती है। यदि सिविल सेवक अपने आप को प्रतिबद्ध करते हैं, अंतिम परिणाम का विश्लेषण करते हैं तो वह ''कर्मयोगी'' बन सकता है।

हमारे ऋषि और मुनि और स्वतंत्रता सेनानियों ने भी केवल जनहित के लिए अपना कर्म किया है। उन्होंने नवनियुक्त सिविल सेवकों से अपील की कि वे जनहित के लिए कार्यशैली/जीवन शैली को अपनाएं।

श्रीमती दीप्ति गौर मुखर्जी, महानिदेशक, आरसीवीपी, नरोन्हा प्रशासन और प्रबंधन अकादमी, भोपाल ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एटीआई में सीओई की अवधारणा, भूमिका और कार्य, लाभ, मानदंड पर विचार साझा किए। साथ ही उन्होंने कुछ मुद्दों को श्रोताओं के सामने चर्चा के लिए रखा।

श्री हरप्रीत सिंह, डीजी (एफएसी), डॉ एमसीआर एचआरडी इंस्टीट्यूट, तेलंगाना ने एच.आर.डी. प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षण और निपुणता के बारे में 2008 से तेलंगाना में एलबीएसएनएए की सहयोगी अकादमी के रूप में अपने अनुभव को साझा किया। श्री सौरभ भगत, महानिदेशक, जे0 एण्ड के0 इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड रूरल डेवलपमेंट, श्रीनगर, जम्मू एण्ड कश्मीर ने डी.ए.आर.पी.जी. और स्ठैछ।। के सहयोग से जम्मू–कश्मीर में राज्य सिविल अधिकारियों के लिए एचआरडी और ब्नदजमत वि म्गबमससमदबम कार्यक्रम करने के अपने अनुभव को साझा किया। उन्होंने श्रोताओं के बीच जम्मू–कश्मीर के सुशासन सूचकांक को भी साझा किया। श्री सौरभ भगत, महानिदेशक, जे0 एण्ड के0 इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड रूरल डेवलपमेंट, श्रीनगर, जम्मू एण्ड कश्मीर और पूनम सिंह, छब्ळळए भारत सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के अपने अनुभवों को साझा किया।

श्री आदिल जैनुलभाई, अध्यक्ष, क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्षता में मिशन कर्मयोगी और प्रशिक्षण के भविष्य पर सत्र केन्द्रित था। अन्य वक्ता थे श्री श्रीनिवास आर. कटिकिथाला, निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी (स्ठैछ।।द्ध, सुश्री सुनीता रानी, प्रोफेसर, स्ठैछ।। और डॉ0 हिताशी लोमाश, निदेशक, ैैण्थ्ैण्ण्

पांचवें सत्र में श्री आदिल जैनुलभाई ने मिशन कर्मयोगी के प्रमुख कार्यक्रम घटकों पर अनुभव प्रस्तुत किया। उन्होंने साझा किया कि अधिकांश सिविल सेवकों को लंबे लेखन को पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। श्री आदिल जैनुलभाई ने रेलवे क्लर्कों, स्टेशन मास्टरों, ग्राहकों/यात्रियों के साथ व्यवहार करने वाले टी.टी.ई. को व्यवहार प्रशिक्षण के बारे में अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने डाक विभाग के कर्मचारियों के प्रशिक्षण को भी साझा किया। इन सभी प्रयासों को करने और प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद, उन्होंने देखा कि परिवर्तन हो रहे हैं। श्रीनिवास आर. कटिकिथाला, निदेशक, एलबीएसएनएए (वीसी) और सुश्री सुनीता रानी, प्रोफेसर, एलबीएसएनएए ने ''देश की सेवा में कर्मयोगियों'' पर अपने अनुभवों को साझा किया। डॉ. हिताशी लोमाश, निदेशक, सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने श्रोताओं के बीच अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने क्षमता निर्माण के लिए महत्वपूर्ण विचार के बारे में चर्चा की,

एसएसआईएफएस संस्थान मिशन कर्मयोगी के मूल सिद्धांतों को कैसे लागू कर रहा है, विशेष रूप से विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण, नियमित और कार्यकाल आधारित प्रशिक्षण के संबंध में उन्होंने चर्चा की।

श्री एस.एन. त्रिपाठी, डीजी, आईआईपीए के साथ डॉ. धाररू मल्होत्रा, एसोसिएट प्रोफेसर–ई गवर्नेंस एंड आईसीटी, प्रो. अशोक विशनदास, प्रोफेसर, आईआईपीए और स्पीकर प्रो0 भारत भूषण, प्रोफेसर, पर्यावरण योजना, यशदा, डॉ कल्पना गोपालन, आईएएस, अपर मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार ने भी विचार व्यक्त किए।

षष्टम् सत्र में श्री एस0एन0 त्रिपाठी, महानिदेशक, डी.ए.आर.पी.जी., और डॉ0 चारु मल्होत्रा ने ''एटीआई के बीच ग्रेडर सिनर्जी'' पर आईआईपीए और 9 एटीआई की भूमिका, इसके व्यवसाय मॉडल, प्रशिक्षण गतिविधियों, मुख्य मुद्दों, संकाय की तैयारी, बुनियादी ढांचे, नेतृत्व समर्थन और प्रतिभागियों के हिस्से पर चर्चा की। ष्ष्ट।६ ।ज्‌ और राज्य सरकारों की भूमिका और जिम्मेदारियों पर भी चर्चा की गई। जनता और सिविल सेवकों को नियंत्रित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए ब्टप्क्19 अवधि के दौरान कुछ केस स्टडी प्रस्तुत किए गए।

सत्र के दौरान, राज्य लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईपीएआरडी)। त्रिपुरा ने संस्थान द्वारा किए गए त्रिपुरा राज्य में गतिविधियों और उपलब्धियों को भी साझा किया। श्रीराम तारनकांति, महानिदेशक, आई.आई.पी.ए, त्रिपुरा ने राज्य में की गई गतिविधियों को साझा किया।

इस सत्र में श्री सोमेन्द्र सिंह, बर्ड फैकल्टी, लखनऊ ने राज्य, केंद्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों को दी जाने वाली गतिविधियों और प्रशिक्षण को साझा किया।

समापन सत्र के दौरान श्री एस.एन. त्रिपाठी, डीजी, आईआईपीए, श्री वी. श्रीनिवास, विशेष सचिव, डीएआरपीजी, डॉ. देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति कार्मिक, उ0प्र0 शासन, श्री एल वेंकटेश्वर लू, महानिदेशक, उपाम, श्री एन.बी.एस. राजपूत, संयुक्त सचिव, डी.ए.आर.पी.जी. ने भाग लिया।

अन्त में डॉ0 देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन ने सभी गणमान्य वक्ताओं, प्रतिनिधियों और प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सम्मेलन के समापन की घोषणा की।

****

DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS AND PUBLIC GRIEVANCES